बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 275

लुटियंस दिल्ली

प्रधानमंत्री को 'लुटियंस दिल्ली' का दिल नहीं जीत पाने का मलाल है। इस शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजों की बनाई नई राजधानी में मौजूद सरकारी इमारतों और बंगलों के लिए होता है। एडविन लुटियंस इसके प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे लेकिन उनके कई विचारों को लागू नहीं किया गया। लुटियंस शुरू में लाल बलुआ पत्थरों के इस्तेमाल, गोल चक्कर बनाने, पेड़ और झाड़ियों के पक्ष में नहीं थे और वह रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन भी नहीं बनाना चाहते थे। सच तो यह है कि नई दिल्ली में बनी अधिकांश इमारतें और बंगले दूसरे वास्तुकारों ने डिजाइन किए थे, लुटियंस ने नहीं। लेकिन यह इलाका लुटियंस दिल्ली ही कहा जाता है।

इस मोदी-विरोधी केंद्र में आखिर कौन लोग रहते हैं? यहां के 19 वर्ग किलोमीटर इलाके में मौजूद करीब 1,000 पुराने बंगलों में से 90 फीसदी सरकार के पास हैं और उनमें मंत्री, सांसद और वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं। मोदी के मलाल की वजह ये लोग तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन लुटियंस दिल्ली का दायरा अब बढ़कर 28 एकड़ तक जा पहुंचा है जिसमें डिप्लोमेटिक एनक्लेव और गोल्फ लिंक भी शामिल हैं। इन इलाकों की गिनती सर्वाधिक पसंदीदा जगह के तौर पर होती है। राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां बंगले की चाहत रखते हैं। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भी सांसद यह इलाका नहीं छोड़ना चाहते हैं। दूसरे शहरों के कारोबारी भी लुटियंस दिल्ली में रिहाइशी आवास खरीदते हैं। फिर भी इसकी कुल जनसंख्या 3 लाख से कम होगी जो 1.6 करोड़ की आबादी वाले शहर के 2 फीसदी से भी कम है। ऐसे में प्रधानमंत्री तो छोड़िए, कोई भी नेता क्यों फिक्रमंद होगा?

दरअसल असली लुटियंस दिल्ली यहां का वास्तु या निवासी नहीं हैं। असल में यह एक मुहावरा है जो लॉबी करने वालों, वकीलों, सेमिनार में जुटने वाले बुद्धिजीवियों, उद्योग मंडलों के इवेंट मैनेजर, सेवारत एवं सेवानिवृत्त राजनयिक, पत्रकार और इंडिया इंटरनैशनल सेंटर (आईआईसी) को अपने-आप में समेटे हुए है।

इसे 'प्रतिष्ठान' भी कहा जा सकता है। यह एक ऐसा 'प्रतिष्ठान' है जो छोटा और खुद ही अपना चयन करने वाला विशिष्ट समूह है और उसके दीर्घकालिक प्राधिकार भी हैं। इसके लिए ब्रिटेन में 'ऑक्सब्रिज' कूटनाम मशहूर था जो देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों से निकले छात्रों के लिए इस्तेमाल होता था। ब्रिटेन में चाहे जो भी सरकार बनाए, शासन और वित्तीय केंद्रों को ऑक्सब्रिज ही चलाते थे। पहली भाषा के तौर पर अंग्रेजी का इस्तेमाल करने वाले और दिल्ली के आधा दर्जन प्रमुख कॉलेजों एवं संस्थानों के पूर्व छात्र भी शैक्षणिक अभिजन की श्रेणी में आते हैं। इनमें से कई लोग किसी न किसी रूप में सरकार का हिस्सा होते हैं और प्रमुख जगहों पर उन्हें आसानी से देखा जा सकता है।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

वाशिंगटन में ऐसे लोगों के लिए 'बेल्टवे' का जिक्र होता है जो असल में एक रिंग रोड है। बेल्टवे के करीब रहने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनका बाकी देश के राजनीतिक मिजाज से कोई नाता नहीं होता है। वैसे दिल्ली के बारे में ऐसी बात सच नहीं है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से ताल्लुक रखने वाले लोग देशव्यापी रुझान के मुताबिक ही मतदान करते हैं। लेकिन लुटियंस दिल्ली का मामला अलग है। जहां वैचारिक रुख तय करने वाले लोग उदारवाद और धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा करते हैं, वहीं मतदाता खेती के असाध्य होने, नौकरियों और अब आवारा पशुओं को लेकर फिक्रमंद हैं जबकि लुटियंस दिल्ली के किसी भी समूह को इनकी चिंता नहीं करनी है। यशवंत सिन्हा कहते थे कि बजट के बाद पूछे जाने सवालों का हजारीबाग में रहने वाले उनके मतदाताओं का कोई लेना-देना नहीं होता है।

मोदी सरकार में भी अरुण जेटली और हरदीप पुरी जैसे लुटियंस दिल्ली वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन मोदी का यह मानना सही है कि इस एनक्लेव में प्रभावी विचार उनकी राय से मेल नहीं खाते हैं। फिर उन्हें मलाल किस बात का है? वह शायद यह है कि भाजपा को अब भी सबल्टर्न (कमतर) माना जाता है। उनकी सरकार कुछ पुस्तकों के पुनर्लेखन, एनजीओ की फंडिंग रोकने, सुब्रमण्यन स्वामी और एस गुरुमूर्ति जैसे बौद्धिक हमलावरों को साथ लाने, पूर्व जनरलों को अपने पाले में करने, टीवी चैनलों पर अपनी आवाज बुलंद करने और जेएनयू जैसे संस्थानों पर दबदबा कायम करने में सफल रही है। फिर भी वह 'प्रतिष्ठान' का निर्माण नहीं कर पाती है। क्या ये सबल्टर्न अब बैस्टिल पर ही धावा बोलेंगे? विडंबना है कि इसका फैसला तो मतदाता ही कर सकते हैं।

बिनय सिन्हा

'नए भारत की रणनीति' में नहीं दिखती रणनीति

नतीजे देने के बजाय कोरी बयानबाजी के नकारात्मक राजनीतिक परिणाम सामने आते हैं। कोई ठोस रणनीति नहीं होने के कारण सभी पहल मनमानी और अस्थायी हैं। बता रहे हैं रथिन रॉय

नीति आयोग ने 'नए भारत के लिए रणनीति @ 75' जारी की है। यह रणनीति 41 अध्यायों में बंटी है। मैं इस बात से चकित हूं कि ऐसा दस्तावेज इस सरकार के कार्यकाल के अंतिम कुछ महीनों में क्यों जारी किया गया है। इसके बावजूद आयोग के नेक इरादे का स्वागत है क्योंकि योजना आयोग को समाप्त किए जाने के बाद भारत के विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रणनीतिक खाका तैयार करने की दिशा में इतना बड़ा प्रयास नहीं किया गया।

शब्दकोष में रणनीति को 'दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बनाई गई कार्ययोजना' के रूप में परिभाषित किया गया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे नीति आयोग के व्यापक दस्तावेज में भी रणनीति देखने को मिलेगी, लेकिन इसे देखकर निराशा ही हाथ लगी।

एक कार्ययोजना बताती है कि क्या और कैसे किया जाना चाहिए। पहला अध्याय वृद्धि के बारे में है, लेकिन मुझे वृद्धि की कोई रणनीति नजर नहीं आती है। इसके बजाय इसमें कहा गया है कि 8 फीसदी वृद्धि हासिल करने के लिए निवेश को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 36 फीसदी करना होगा और निर्यात को डॉलर में वर्तमान स्तर से करीब दोगुना करना होगा।

दस्तावेज में ऐसा कोई विश्लेषण नहीं है, जो यह बताता है कि आयोग यह वांछित वृद्धि दर क्यों हासिल करेगा और ये विशेष लक्ष्य ही क्यों (30 या 40 फीसदी क्यों नहीं? तिगुना निर्यात क्यों नहीं?) इसमें आर्थिक तथ्य और उनके पीछे तर्क सतही हैं। उदाहरण के लिए इसमें तर्क दिया गया है कि सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के लिए कर-जीडीपी अनुपात को 17 फीसदी से बढ़ाकर 22 फीसदी करना होगा। लेकिन साथ ही इसमें ऋण-जीडीपी अनुपात को कम करने की बात कही गई है, जिसके लिए राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करने की जरूरत है।

इसमें साफ तौर पर संतुलन साधने की कोशिश दिखती है। कर-जीडीपी अनुपात में बढ़ोतरी का इस्तेमाल वर्तमान सरकार के खर्च को बढ़ाने और कर्ज को घटाने में किया जा सकता है, लेकिन दोनों मकसद हासिल करना संभव नहीं है। आयोग के दस्तावेज में वांछित मकसद (कर प्रशासन में सुधार और सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी) हासिल करने के लिए कई बातें कही गई हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि इन्हें कैसे हासिल किया जाएगा।

इसमें कई अस्पष्ट बातें भी कही गई हैं। उदाहरण के लिए 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों पर होने वाले पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के अनुमानों से बाहर रखा जाना चाहिए।' असल में ऐसा होता है। स्कूल की इमारतों आदि को पूंजीगत व्यय में गिना जाता है। 'निर्यात की रणनीति' को लेकर 'लॉजिस्टिक क्षेत्र पर केंद्रित प्रयासों की जरूरत, 'घोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सुधार लाकर संपर्क को सुधारना और दक्षिण एशिया के साथ आर्थिक संबंधों में प्रगाढ़ता की संभावनाएं तलाशने' जैसी बातें कही गई हैं।

ऐसी बातों में कोई रणनीतिक तथ्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति इससे विपरीत बात (संपर्क कम करने या आर्थिक सहयोग प्रगाढ़ न करने) नहीं कहेगा। अमूमन ऐसे बयान नौकरशाह देते हैं, जिनका इस्तेमाल रणनीति दिशा की सूझबूझ की कमी को ढंकने में किया जाता है। कौशल और श्रम सुधारों पर कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं, जो यह नहीं बताते कि इनसे कैसे रोजगार बढ़ेगा।

तकनीक पर केंद्रित अध्याय में तकनीकी नौकरशाही को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। (उदाहरण के लिए 'एक अधिकार प्राप्त संस्था... जो इस विज्ञान के प्रबंधन का ठीक से संचालन कर सके।') उद्योग से जुड़े अध्याय एक ठोस सुझाव दिया गया है। यह सुझाव परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक पोर्टल है। नीति आयोग के दस्तावेज का दूसरा अध्याय किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर है। यह इस दस्तावेज में सबसे अच्छा है। इसमें कानून में कुछ विशेष संशोधनों और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की जगह कृषि न्यायाधिकरण बनाने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की जगह न्यूनतम आरक्षित कीमत लागू करने का भी सुझाव दिया गया है।

सभी के लिए आवास के बारे में सरकार से कहा गया है कि वह धन जुटाना जारी रखे और दिल्ली में ईस्ट किदवई नगर जैसी अन्य परियोजनाएं लाई जाएं। बाकी सभी सुझाव- खाली सरकारी जमीन के इस्तेमाल जैसी पुरानी सिफारिशों का दोहराव है। बुनियादी के अध्याय में एक विशेष सुझाव दिया गया है- अन्य सब्सिडी की जगह एक अग्रिम कृषि सब्सिडी लागू की जाए। हालांकि यह साफ नहीं है कि इसका सुझाव इस अध्याय में क्यों दिया गया।

भूतल परिवहन, रेलवे, नागरिक उड्डयन, जहाजरानी एवं बंदरगाह और लॉजिस्टक के अध्यायों में भी यही स्थिति है। इन अध्यायों की सिफारिशों में या तो वर्तमान परियोजनाओं को जारी रखने या और सरकारी संस्थाएं बनाने की बात कही गई है। समावेश पर जो अध्याय है, उसमें छात्रों के मानसिक दबाव को दूर करने के लिए कुछ अच्छी सिफारिशें दी गई हैं। लेकिन इसमें भी शेष दस्तावेज की तरह रणनीतिक सामग्री का अभाव है। दुर्भाग्य से कौशल विकास और स्वास्थ्य के अध्यायों में भी यही स्थिति है। हालांकि सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा के अध्याय में कम से कम कुछ ठोस सुझाव जरूर दिए गए हैं।

मैं दस्तावेज के अन्य अध्यायों का भी जिक्र कर सकता हूं, लेकिन यह बातों का महज दोहराव साबित होगा। इस दस्तावेज में मेरे लिए जो अहम बातें हैं, उनका जिक्र कर रहा हूं। इसमें आर्थिक उद्देश्यों पर राजनीतिक स्पष्टता है, लेकिन इस बारे में कोई रणनीतिक योजना नहीं है कि इन्हें हासिल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। प्रस्तावित 'समाधान' अपने आप में अकेले हैं। इसमें विकास की आकांक्षा है, लेकिन कोई समन्वित विकास की रणनीति नहीं है।

यह कमजोरी संस्थागत है। नतीजे देने के बजाय कोरी बयानबाजी के नकारात्मक राजनीतिक परिणाम सामने आते हैं। इसके अलावा यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें रणनीति नजरिये में अस्पष्टता से लाभ मिलता है। कोई ठोस रणनीति नहीं होने के कारण सभी पहल मनमानी और अस्थायी हैं। इससे अपने हितों के लिए काम करने वाले लोगों की ताकत बढ़ती है। राजनेताओं की मंशाओं के लिए दिखावटी पहल और कार्यक्रम आयोजित कर जुबानी तसल्ली दी जाती है। इससे वांछित नतीजे सामने नहीं आते हैं, जिसकी कीमत राजनेताओं को चुकानी पड़ती है। लेकिन यह कीमत कार्यक्रमों को लागू करने वाले कार्याधिकारियों और निहित हित वाले लोगों को नहीं चुकानी पड़ती।

वांछित नतीजे नहीं दे सकने वाली किसी कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा दंडित किए जाने का मतलब है कि बहुत कम योग्य व्यक्ति सरकार के साथ काम करना और सत्ता के सामने सच्चाई पेश करना चाहते हैं। इससे कार्याधिकारियों का राजनीतिक प्रबंधन और कमजोर होता है। इस 'रणनीतिक' दस्तावेज की कमजोरी फिर से इस दुष्चक्र को लेकर चेतावनी देती है। यह दस्तावेज आगामी सरकारों के लिए इस जरूरत पर बल देता है कि सुधारों को गंभीरता से लिया जाए। जब सत्ता में हों तो नतीजों के लिए काम करना चाहिए और केवल आत्म-प्रशंसा वाले कार्यक्रमों से उल्लासित नहीं होना चाहिए।

(लेखक राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान के निदेशक हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

नए साल में मीडिया जगत के लिए नए संकल्प

मीडिया मंत्र
वनिता कोहली-खांडेकर

यह वक्त संकल्प करने का है। यहां पर 1.47 लाख करोड़ रुपये के आकार वाले भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के बारे में भी दो संकल्प पेश कर रहे हैं। क्या भारतीय मीडिया की बड़ी कंपनियों चला रहे पुरुष और महिलाएं तदर्थ तरीके से काम करने के बजाय अधिक मजबूत, बेहतर और सूचना-आधारित लॉबी करने का संकल्प ले सकते हैं? और, क्या वे केवल सरकार और नियामकों के बजाय सभी हितधारकों से संचार करने का संकल्प ले सकते हैं?

ताजा मामला भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के 2016 के उस आदेश से संबंधित है जिसे फिलहाल लागू करने की कोशिशें की जा रही हैं। यह अब भी रहस्य बना हुआ है कि यह आदेश क्यों आया? भारत एक बेहद प्रतिस्पर्द्धी टेलीविजन बाजार है। यहां पर टीवी वितरण तीन तकनीकों- केबल, डीटीएच एवं ऑनलाइन पर आधारित है और इनमें से हरेक का दायरा व्यापक है। देश में 867 चैनल प्रसारित हो रहे हैं। इसके बावजूद भारत में प्रति उपभोक्ता औसत राजस्व पूरी दुनिया में सबसे कम है। ऐसे में इस तरह का शुल्क आदेश जारी करने की वजह एक पहेली ही है। विकसित बाजारों के नियामक आम तौर पर किसी नए नियम या नीति को लागू करने के पहले उसके असर, लागत और होने वाले लाभों का विश्लेषण करते हैं। उपभोक्ता समूहों, कारोबार जगत और सभी हितधारकों को पता होता है कि इससे कौन जुड़ा हुआ है? सभी हितधारकों के बीच स्वामित्व का एक अहसास होता है।

भारत में निजी चैनलों के 25 वर्ष और केबल वितरण शुरू होने के 30 वर्ष बाद भी उपभोक्ताओं, मीडिया और नियामकों के बीच इस उद्योग के कामकाज संबंधी बुनियादी जानकारियों की कमी है। क्या आप एक उपभोक्ता होने के नाते यह जानते हैं कि भारत में टीवी की कीमतें दुनिया भर में शायद सबसे कम हैं? क्या भारत का कारोबारी मीडिया यह जानता है कि टीवी उद्योग में 16.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर रोजगार मिला हुआ है और यह उद्योग हर साल अरबों रुपये का कर चुकाता है? क्या टेलीविजन उद्योग की गतिविधियां कवर करने वाले पत्रकार यह समझते हैं कि टीवी कार्यक्रमों की रेटिंग किस तरह तय होती है और किस तरह कीमतें निर्धारित की जाती हैं? अगर एक साल में लाखों उपभोक्ता डीटीएच या केबल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते हैं तो रोजगार, कर और नौकरी की संभावनाओं के लिए इसके क्या मायने हैं? आखिर 66,000 करोड़ रुपये के इस उद्योग का व्यापक प्रभाव क्यों नहीं दिखता है? इसकी वजह यह है कि इसने कभी भी उन लोगों से संवाद नहीं किया है जो सर्वाधिक अहमियत रखते हैं। ब्रिटेन में रचनात्मक उद्योगों के फलने-फूलने में प्रोड्यूसर्स अलायंस फॉर सिनेमा ऐंड टेलीविजन जैसे संगठनों का भी बड़ा हाथ रहा है। ब्रिटेन में उपभोक्ताओं को पता होता है कि उन्हें बीबीसी देखने के लिए रोजाना कितना भुगतान करना है। भारतीय प्रसारण उद्योग में शायद एक ही बार ऐसा हुआ है कि समूचा उद्योग वर्ष 2011 में केबल डिजिटलीकरण अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर उपभोक्ताओं से मुखातिब हुआ था।

विरोध और निरर्थक विचारों का खमियाजा भुगतने वाले फिल्म जगत पर भी यही बात लागू होती है। फिल्म उद्योग में 7 लाख लोगों को सीधे या परोक्ष रोजगार मिला हुआ है और यह अपनी कमाई का एक-तिहाई हिस्सा कर के रूप में चुका देता है। लेकिन कुछ वजह से ये दोनों उद्योग अपने विषयवस्तु के चलते करोड़ों लोगों के दिमाग पर असर डालने की क्षमता रखने के बावजूद समाज, अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं को दिए गए योगदान की चर्चा नहीं कर पाते हैं। क्या ये उद्योग इस साल इस काम को बेहतर ढंग से अंजाम देने का संकल्प लेते हैं?

कुछ समय से नफरत, अपशब्द और क्रूरता से भरा आचरण सोशल मीडिया का प्रचलित परिदृश्य है। अब यह पता चला है कि सरकार सोशल मीडिया फर्मों पर इन प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने के लिए तकनीक का सहारा लेने का दबाव बना रही है। निश्चित रूप से उन्हें ऐसी बातों को हटाना चाहिए लेकिन ऐसी बातें समाज में पहले से ही मौजूद हैं। ट्विटर या फेसबुक तो महज प्लेटफॉर्म हैं। इन्हें कॉफी शॉप की तरह देखना चाहिए जहां हम जाते हैं। वह जगह हमें चीखने, चिल्लाने और गलत भाषा के इस्तेमाल के लिए नहीं उकसाती है। हम लोग ही वहां जाकर गलत बरताव करने लगते हैं। पहले हमारा शिष्ट आचरण हमें अपने पूर्वग्रह या कट्टरता दिखाने से रोक लेता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनका प्रदर्शन फैशन जैसा हो गया है। गलत सूचना के आधार पर नफरत फैलाने वाला आचरण आज ईमानदार या खरी बात करने वाला माना जाता है।

अगर हम शिष्टता, सभ्यता एवं अच्छे आचरण को प्रतिष्ठा का प्रतीक बनाने में सफल रहते हैं तो हम अपने आसपास क्या बदलाव ला पाएंगे? फिर नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल समाज में शालीनता लाने के लिए भी किया जा सकेगा। याद रखें कि भारत ने मतदान को प्रतिष्ठा का प्रतीक और गर्व एवं उत्तरदायित्व की निशानी बनाकर पिछले दशक में मतदान प्रतिशत में काफी इजाफा किया है। ऐसा इसलिए हो पाया कि विज्ञापन फिल्मों, रंगमंच, टेलीविजन और फिल्मों ने मतदान के बाद स्याही लगी उंगली दिखाने को एक फैशन बना दिया था। ये तस्वीरें शायद यही संदेश देती रही हैं कि जब अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान मतदान करने जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसे में हमारा दूसरा संकल्प यह होना चाहिए कि समाज में घृणा एवं नफरत का मुकाबला करने के लिए हम अपने सबसे अच्छे एवं बेहद सभ्य आचरण का प्रदर्शन करें। मिशेल ओबामा ने अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कहा था, 'जब वे नीचे गिरते हैं तो हम ऊपर हो जाते हैं।' हमारे समाज में निश्चित रूप से नफरत और तीखेपन से भरे लोगों की तुलना में संयत और शांति चाहने वाले लोगों की संख्या अधिक है। लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर ऐसे लोग नजर नहीं आए हैं।

कानाफूसी

मंत्रालयों से मुलाकात के लिए तैयारी जरूरी

पंद्रहवें वित्त आयोग के सदस्यों ने नए साल में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। चौदहवें वित्त आयोग का गठन वर्ष 2013 में हुआ था और अब पांच साल बाद ये मुलाकातें हो रही हैं। विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों को पुरानी फाइलें पढ़ते हुए देखा जा रहा है, जिससे वे आयोग के प्रतिनिधियों से सही तरह से मुलाकात कर सकें। कुछ अधिकारियों का मानना है कि ये बैठकें भी सालाना बजट बैठकों की तरह ही होंगी लेकिन उन्हें आयोग के सदस्यों ने याद दिलाया कि वित्त आयोग का एक अलग एजेंडा है और उन्हें उसके अनुसार अपनी वरीयताएं तैयार करनी होंगी।

भोजन का स्वाद

नए साल के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में कई जगह गुरुवार दोपहर को भोज कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा आयोजित भोज में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और पत्रकारों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता प्रफुल्ल पटेल द्वारा आयोजित भोज महागठबंधन के नेताओं के मिलने-जुलने का कार्यक्रम बन गया। लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने अपना राजनीतिक महत्त्व और पहुंच का प्रदर्शन करने के लिए इसमें भाग लिया। बहुत से लोग मुरादाबादी दाल का लुत्फ उठा ले रहे थे। विपक्षी पार्टियों से भोज में शामिल होने वाले नेताओं में शरद पवार, फारुक अब्दुल्ला, अहमद पटेल, सीताराम येचुरी, सतीश चन्द्र मिश्रा, मीसा भारती, जया बच्चन, दिनेश त्रिवेदी और एम के कनिमोझी शामिल थे।

आपका पक्ष

सैटेलाइट से दुरुस्त होगी संचार प्रणाली

देश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मोबाइल नेटवर्क या संचार सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों या ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में संचार साधन की कमी है। ऐसे में दूरसंचार विभाग सैटेलाइट नेटवर्क लगाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए दूरसंचार विभाग अंतरिक्ष विभाग से बातचीत कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अबतक 35 संचार सैटेलाइट छोड़े हैं। सैटेलाइट का विभिन्न संस्थान या व्यापारिक संगठन संचार सेवा के लिए उपयोग करते हैं। इन सेवाओं का इस्तेमाल मुख्य रूप से सैटेलाइट फोन, द्वीप तथा पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के लिए किया जाता है। इससे दुर्गम स्थानों पर भी संचार सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार की

दूरसंचार विभाग सैटेलाइट नेटवर्क लगाएगा जिससे दुर्गम क्षेत्रों में संचार स्थापित हो सके

देश भर में शत प्रतिशत कनेक्टिविटी की योजना है। ऐसे में सैटेलाइट सेवा का इस्तेमाल करके इस योजना को सफल बनाया जा सकता है। आमतौर पर संचार के लिए केबल का उपयोग किया जाता है। लेकिन केबल तार बिछाने तथा दुर्गम स्थानों पर इसकी पहुंच नहीं होने से संचार व्यवस्था कायम नहीं हो पाती है। इसके अलावा केबल तार बिछाने में काफी खर्च भी बैठता है। एक शहर को केबल तार के जरिये दूसरे शहर को जोड़ने के लिए कई किलोमीटर लंबी केबल तार लगेगी तथा इसे बिछाने का खर्च अलग से लगेगा। ऐसे में सैटेलाइट से कम खर्च पर संचार स्थापित किया जा सकता है। अगर दूरसंचार विभाग द्वारा सैटेलाइट नेटवर्क लगाया जाता है तो विमानों में भी मोबाइल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। विमानों में मोबाइल सेवा देने की योजना पर बातचीत चल रही है। ऐसे में विमान के सफर में भी मोबाइल संपर्क सुनिश्चित हो सकेगा। इस योजना से देश के सुदूरवर्ती दुर्गम क्षेत्रों में भी संचार स्थापित हो सकेगा तथा मोबाइल फोन काम करने लगेंगे।

किशोर कुमार, नोएडा

नोट बदलने की प्रक्रिया गलत

सरकार ने अबतक 10, 50, 100, 200, 500 और 2,000 रुपये के नए नोट जारी किए हैं। लेकिन अब 20 रुपये के नए नोट भी जारी करने की योजना है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि इस प्रकार नोटों के रूप तथा स्वरूप बदलने से देश को क्या फायदा होगा। क्या नए नोट छापने की प्रक्रिया अपव्यव की संज्ञा में नहीं आएगा। क्योंकि इनकी छपाई, रंग तथा कागज पर करोड़ों रुपये का खर्च आता है। अगर इसपर हुए खर्च को किसी अन्य नई योजना प्रारंभ करने पर लगाया जाए तो उससे आजीवन भर उसका लाभ जनता को प्राप्त होगा। देश में रोजाना बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। अत: इसके लिए रोजगार सृजन करने की दिशा में कार्य होना चाहिए।

घेवरचंद गोदीका, जयपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।